कलापों, रोजगार और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की समस्याओं की जांच करने हेतु सरकार पहले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन कर चुकी है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नगरों का विकास

2451. **चौधरी हरि सिंह :**
श्री शांति त्यागी :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों के लिए 1990-91 के दौरान कितनी राशि आबंटित की गई है और ऐसे जिलों में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अधीन आने वाले जिले की निधि आबंटन में कोई प्राथमिकता दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे जिले का नाम क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान निधियों का जिलावार नियतन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) निधियों के नियतन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतगत किसी भी जिले को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। तथापि, क्षेत्र में निम्नलिखित चुनींदा कस्बों को विकास में प्राथमिकता दी गई है :—

उत्तर प्रदेश में—मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर और खुर्जा :

हरियाणा में-पानीपत, रोहतक, रिवाड़ी, झाड़सेड़ा और पलवल ; और राजस्थान में-अलवर तथा भिवाड़ी।

Rereservation of Plots in the big cities of the Country

2452. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SOM PAL:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that dereservation of plots in big cities in the country is actively encouraged by vested interests, particularly builders lobby thereby harming the urban development if so, what are the measures contemplated by Government to prevent such dereservation; and

(b) whether it is also a fact that such dereservation of plots is leading to cutting down of the infrastructure lay outs of schools, parks, hospitals and roads etc. and helps increase crowding and congestion?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) and (b) Dereservation of plots is within the ambit of the local bodies and state Government concerned and the Government of India does not have any role to play in the matter.

Unauthorised Construction in Ashok Vihar

2453. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints about the unauthorised construction in the DDA flats in Pocket 'A' phase-III, Ashok Vihar, Delhi;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government have taken/proposed to take in the matter?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) and (b) The DDA has reported that complaints have been received regarding unauthorised construction made in flats No. 19-B and